THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) (a) to (c) the item-wise and country-wise details of exports and imports are published by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) in their publication "Foreign Trade Statistics of India (Principal Commodity & Countries)". The Policy and Procedures for Export and Import are contained in Export and Import Policy, 1992—97 and the Handbook of Procedures, (Volume I & II), 1992—97. The copies of above publications are available in Parliament Libarary.

National Authority for Elimination of Child Labour

*310. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether at a meeting of National Authority for Elimination of Child Labour (NAECL) held on 10th July, 1995 he had rejected the ILO's offer for fudns for the progremmes like Elimination of Child Labour; and

(b) if so, the facts and circumstances leading to such refusal?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) Realising the magnitude of the problem and the substantial funding required, Government have considered it appropriate to provide sufficient funds themselves through budget for various programmes aimed at eliminating child labour in hazardous occupations. It is also for this reason that Government have decided to discontinue receiving funds from the ILO for the purpose. It has, however, been decided that the on-going externally funded projects would run their whole implementation period. This decision was conveyed to the ILO authorities and the members of the National Authority for Elimination of Child Labour were also apprised of the development at its meeting on 10th July, 1995.

लेवी चीनी का आवंटन

*311. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 31 जुलाई, 1995 और 14 अगस्त, 1995 को राज्य सभा में क्रमशः अतारांकित प्रश्न 2 और 1414 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993, 1994 और 1995 के 30 नवम्बर तक आवंटित लेवी चीनी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या बिहार सरकार ने लेवी चीनी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है; यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान 30 नवम्बर तक लेवी चीनी के आवंटन का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। *(नीचे देखिए)*

(ख) बिहार सरकार ने 1991 की जनगणना के आधार पर आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उन्हें प्रतिमाह किए जाने वाली लेवी चीनी के आवंटन को बढ़ाकर 37000 मी॰ टन किए जाने का अनुरोध किया था। 1991 की जनसंख्या के आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लेवी चीनी के कोटे में 1 जनवरी, 1996 से संशोधन करने का निर्णय किया गया है। तदनुसार, बिहार को जनवरी, 1996 माह से मासिक लेवी चीनी का 36707 मी॰ टन कोटा दिया गया है।